

कांग्रेस नेता का पीएम मोदी पर तंज.....ट्रंप नहीं आ रहे इसलिए जी20 लीडर्स समिट में जा रहे

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें जी20 लीडर्स समिट के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हुए हैं। जिसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा आयोजित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने तंज करते हुए कहा कि अगला जी 20 सम्मेलन अमेरिका

में आयोजित होगा और तब देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या रास्ता चुनते हैं।

पीएम मोदी शुक्रवार को 3 दिवसीय यात्रा पर द.अफ्रीका रवाना हुए, जहां वे जोहानिसबर्ग में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वे 'वसुधैव कुटुंबकम्' तथा 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' की भावना के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले हैं।

कांग्रेस नेता रमेश ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी आज और

मंत्री माकों रुबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के जी20 थीम-एकचुटता, समानता और सतत विकास का विरोध करता है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह अमेरिका-विरोधी है। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा, जी20 की अध्यक्षता हर साल बदलते रहती है।

भारत ने यह अध्यक्षता नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से ली और नवंबर 2024 में ब्राजील को सौंपी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को यह अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है, जो इस बार शिखर सम्मेलन में मौजूद ही नहीं है।

उन्होंने कहा, अगला जी20 शिखर सम्मेलन एक साल बाद अमेरिका में होगा।

तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता हो चुका होगा। लेकिन जिस तरह ट्रंप

भाजपा सरकार आठवीं दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का राजनीतिकरण कर रही :आप

नई दिल्ली

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) ने रेखा गुप्ता सरकार और आठवीं दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर निशाना साधा है। आप का आरोप है कि भाजपा सरकार आठवीं दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का राजनीतिकरण कर रही है। आप के अनुसार, भाजपा सरकार कई विशेष बैठकें बुलाकर और फांसी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को नोटिस जारी करके दिल्ली के गहराते पर्यावरणीय संकट और चरमराती सार्वजनिक सेवाओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए विधायी समितियों का इस्तेमाल कर रही है। आप ने कहा कि भाजपा विधायी समितियों को हथियार बना रही है।

आप ने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही के मूल आधार पर ही सवाल उठाया है। आप ने बताया कि समिति द्वारा उद्धृत घटना अगस्त 2022 में सातवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिसे फरवरी

केरल-यूपी में एसआईआर को

लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को भेजा नोटिस

मांगा जवाब, 26 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा कोर्ट

नई दिल्ली

केरल और यूपी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर उठते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा लागू की जा रही वह कवायद है जिसके तहत मतदाता सूची की गुप्त तरीके से पहचान और सत्यापन किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया को लेकर कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर सवाल खड़े हुए हैं और इसको चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं।

केरल सरकार, राज्य की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य की तरफ से दायर याचिका में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 9 और 11 दिसंबर के लिए पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया चलाना न तो व्यावहारिक है और न ही निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के अनुकूल है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक चुनाव



असली वोटों और कुल वोटरों की संख्या में अंतर के दावों को आयोग ने किया खारिज

गलत डेटा में पोस्टल बैलेट को शामिल नहीं किया, जिससे शक पैदा हुआ

नई दिल्ली

बिहार विधानसभा चुनावों में असली वोटों और कुल वोटरों की संख्या में भारी अंतर के बड़े दावों के बीच, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मिसमैच थ्योरी को खारिज कर दिया। आयोग ने झूठे दावों को उजागर करने के लिए पोस्टल बैलेट समेत पोलिंग डेटा का हवाला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटरों

की कुल संख्या से ज्यादा थी, जिससे पोलिंग प्रोसेस में गड़बड़ी और धोंधली का पता चलता है।

दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी अपनी फाइनल लिस्ट में कुल 7.42 करोड़ वोटर्स दिखाए थे, लेकिन 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खत्म हुए मतदान के बाद पोल पैनल ने अपने बयान में कुल वोटर्स की संख्या 7.45 करोड़ दिखाई। खस बात यह है कि चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को



गए, जिनमें से 23,918 रिजेक्ट हो गए। ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों में कुल 9,10,730 वोटरों ने नोटा चुना। पोल पैनल ने कहा कि ईवीएम वोट और पोस्टल बैलेट

देश के प्रथम प्रधानमंत्री

नेहरू के कार्य ऐतिहासिक अभिलेख नहीं

बल्कि राष्ट्र की विकसित अंतरात्मा को दर्शाते हैं

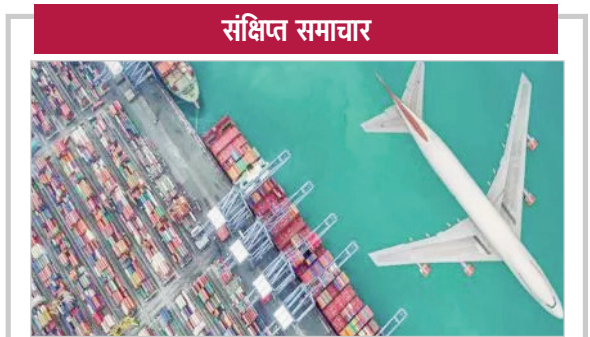
भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली दिशासूचक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के कार्य केवल ऐतिहासिक अभिलेख नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र की विकसित होती अंतरात्मा को दर्शाते हैं, जो उसके साहस, शंकाओं और आकांक्षाओं को समेटे हुए है। संग्रह के महत्व पर अपने विचार साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू के लेखन आधुनिक भारत को आकार देने वाली चुनौतियों और विजयों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा- नेहरूजी के लेखन केवल इतिहास नहीं हैं, वे भारत की विकसित होती अंतरात्मा का अभिलेख हैं। हमारे राष्ट्र की



हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी संसद को सौंपी गई एक हस्तिया रिपोर्ट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह मई में चार दिन के संघर्ष के दौरान भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता के दावे का समर्थन करती है।

हालांकि, पाकिस्तान के मुख्य सहयोगी चीन ने इस रिपोर्ट को भ्रामक जानकारी करार देते हुए खारिज कर दिया। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक कार्यक्रम में शरीफ ने सेना प्रमुख असीम मुनिर के नेतृत्व की भी सराहना की।

हालांकि, पाकिस्तान के मुख्य सहयोगी चीन ने इस रिपोर्ट को भ्रामक जानकारी करार देते हुए खारिज कर दिया। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक कार्यक्रम में शरीफ ने सेना प्रमुख असीम मुनिर के नेतृत्व की भी सराहना की।



भारत में मेटल और माइनिंग शेयरों का भविष्य बेहतर, रिपोर्ट में बताया गया

नई दिल्ली भारत में घरेलू स्तर पर अच्छी मांग के कारण मेटल और माइनिंग शेयरों का भविष्य बेहतर दिख रहा है और इन्हें वैश्विक मेटल कंपनियों के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहेगा। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि समृद्ध संसाधन भंडार और सहायक नियामक नीतियों के कारण, इस क्षेत्र के लिए यह एक अच्छा वर्ष रहा है, और आगे भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। रिपोर्ट में बताया गया, यह शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से प्रेरित मजबूत, टिकाऊ मांग का परिणाम है। देश के विशाल लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और जस्ता भंडार भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर सबसे कम लागत वाले उत्पाद बनाते हैं और सहायक नियामक नीतियां विशेष रूप से चीन से कम लागत वाले आयातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक शोध फर्म ने बताया कि चीन की कैपेसिटी कैप और ग्लोबल डिमांड में स्थिरता की वजह से एल्युमिनियम उसकी पहली पसंद है। इतना ही नहीं चांदी को लेकर भी हमारा नजरिया सकारात्मक है और उम्मीद है कि अधिक मांग को देखकर कीमतें मजबूत रहेंगी। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टील मार्केट है, लेकिन डिमांड के सीजनल होने और चीन में स्टील का कम प्रोडक्शन होने की वजह से हम स्टील स्टॉक्स को अधिक साइबिलकल मानते हैं। रिपोर्ट में प्रीमियम वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स का जिक्र है, जैसे कि भारतीय मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स को बड़े मार्केट्स के हिसाब से री-रेटिंग की गई है। बैलेंस शीट्स की मजबूत हैं क्योंकि कंपनियों ने डिलेवरेज किया है, और लॉन-टर्म आउटलुक अच्छा है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में मेटल की मांग बढ़ रही है। हालांकि, रिपोर्ट में चीन या यूएस में मंदी, ग्लोबल ग्रोथ में तैज गिरावट और मजबूत यूएस डॉलर से नुकसान के रиск की चेतावनी दी है, जिससे कंपनियों पर कैश फ्लो का दबाव बन सकता है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश का दूसरा जेन-जी थीम आधारित पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन

नई दिल्ली भारतीय डाक विभाग ने देश के शैक्षणिक संस्थानों के डाक घरों को नई पीढ़ी से जोड़ने की मुहिम में लगा है। इस अभियान के तहत विभाग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश का दूसरा जेन-जी थीम आधारित पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। इसका मकसद छात्रों और युवाओं के जीवन के साथ कदम से कदम मिलाने का है। इस पोस्ट ऑफिस में परिवर्तन कर जेन-जी को ध्यान में रखकर फिर से डिजाइन किया है। पोस्ट ऑफिस को रि-डिजाइन करने में मिरांडा हाउस एडवाइजरी फाइन आर्ट्स सोसाइटी की मदद ली गई है। पोस्ट ऑफिस को युवा आधारित पहचान देने के लिए इसमें दीवार पर चित्र, फ्री वाई-फाई, पार्सल पैकिंग सर्विस जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। दरअसल, पोस्ट ऑफिस का कायाकल्प सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसमें अगले साल जनवरी तक देश के 46 शैक्षणिक संस्थानों को नया रूप देने का लक्ष्य बनाया है। इससे पहले डाक विभाग इस मुहिम के तहत आईआईटी दिल्ली के पोस्ट ऑफिस को भी री-लांच कर चुका है। मोदी सरकार का कहना है कि इस मुहिम के जरिए वे देश के युवाओं से कनेक्ट करना चाहती है। यहां स्टूडेंट्स के लिए स्पीड पोस्ट छूट जैसी सुविधाएं हासिल की जा सकती है। यह परिवर्तन एक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ छात्र भागीदारी है, जिसमें भारतीय डाक छात्रों को ब्रांड एंबेसडर, डिजाइन तत्वों के सह-निर्माता और सोशल मीडिया आउटरीच में सहयोगी के रूप में शामिल करता है।

स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में रखने का निर्देश, सोनाली खुश नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से

मुंबई अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक सोनाली बेंद्रे ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर चिंता जाहिर की है, जिसमें रेलवे स्टेशन, पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है। सोनाली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने विचार रखे हुए कहा कि देश में इतने सारे कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम उपलब्ध नहीं हैं। इतने सारे कुत्तों को एक साथ रखने से उनमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। जो लोग कुत्तों से नफरत करते हैं, वे इस फैसले का गलत फायदा उठाकर गलत तरीकों से उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। लोकल लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाकर प्यार जताते हैं। शेल्टर होम में जाने के बाद यह सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि उन्हें खाना खिलाया गया है या नहीं, जिससे उनकी देखभाल प्रभावित होगी। सोनाली ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- वे सुरक्षा करते हैं, साथ देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। इस तरह का एक भी फैसला हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पशु प्रेमियों ने विरोध किया था। फैसले के खिलाफ याचिका भी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने 7 नवंबर को इस फैसले में बदलाव करने से इंकार किया।

विदाई समारोह में सीजेआई गवर्नर ने ऐसा क्या कहा, पूरा कोर्टरूम ठहाकों से गूंज उठा

नई दिल्ली

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवर्नर 23 नवंबर (रविवार) को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए शुक्रवार उनका अंतिम वर्किंग डे था। सुप्रीम कोर्ट ऐडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने गुरुवार को उनके लिए विदाई समारोह रखा था। कोर्टरूम नंबर 1 में उनकी अंतिम औपचारिक सुनवाई के दौरान, एक वकील ने उन्हें सम्मान देने के लिए उन पर फूल बरसाने की तैयारी की। जैसे ही सीजेआई गवर्नर ने फूल देखकर तुरंत वकील को रोक कर कहा, नहीं नहीं, इस फेंकिप नहीं। इन फूलों को किसी को दे दीजिए। इस पर पूरा



का श्रेय डॉ. आम्बेडकर और संविधान को दिया, जिसके कारण ही एक साधारण पृष्ठभूमि का लड़का इस पद तक पहुंच सका। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय संविधान के चार आधारभूत सिद्धांतों - न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के अनुसार जीने की कोशिश की है।